प्रदेश के सीतापुर जिले के जिला उद्योग केन्द्रों से बैंकवार कितने और किन व्यक्तियों के नाम ऋणों की मंजूरी हेतु सिफारिश की गयी है ;

(ग) क्या उन सभी बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय 15 अगस्त, 1983 को शिक्षित बेरोजगार युवकों के वास्ते घोषित स्वरोजगार योजना से है। इस योजना के अधीन जिला उद्योग केन्द्र (डी०आई०सी०) नोडीय एजेंसियों के रूप में कार्य करते है तथा आवेदनों की जांच एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) द्वारा की जाती है। बैंक कृतिक बल द्वारा सिफारश किए गये आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् मंजूरी दिए जाने से पूर्व उनकी पुनः जांच करते हैं।

(ख) अखिल भारतीय स्तर की वर्तमान सूचना प्रणाली में जिला जिला-वार सूचना नहीं रखी जाती, इसलिए जोधपुर तथा सीतापुर जिलों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध राज्यों में 1983-84 के दौरान इस योजना की प्रगति इस प्रकार थी :—

राज्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत मामले		संवितरण	
	संख्या	संख्या	राशि (लाख रुपये)	मामलों की राशि	राशि (लाख रुपये)
राजस्थान	10000	15054	2365.30	10691	150245
उत्तर प्रदेश	36000	36857	5382.82	23614	2969.33

(ग) और (घ) : मंजूर किए गए सभी मामलों में संवितरण मार्च, 1984 से पहले नहीं किया जा सका क्योंकि बहुत अधिक संख्या में आवेदन वित्तीय वर्ष के अंत में मंजूर किये गये थे। बैंकों को मंजूर किए गये सभी मामलों में तेजी से संवितरण किये जाने के अनुदेश दे दिये गये हैं।

Assessment of Scheme for giving Additional Import Licences to Entrepreneur-Merchant Exporters

*387. SHRI S.A DORAI SEBASTIAN:

SHRI ARJUN SETHI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether a survey covering various trade centres has revealed that the scheme for giving additional import licences to Entrepreneur-Merchant Exporters, has failed to inspire exporters; and

(b) if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) No, Sir. Government has not conducted such a survey. The Scheme of "Special Facilities to Entrepreneur-Merchant Exporters (EMEs) exporting products manufactured by SSI units, Cottage Industries" envisages grant of Additional licences in 1985-86, to EMEs on the basis of 5 per cent of the f.o.b. value of their exports of

select products manufactured by SSI/Cottage Sector units in 1984-85, subject to certain prescribed conditions.

देश में कृत्रिम रेशे का उत्पादन

389. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक प्रकार के देशीय और आयातित कृत्रिम रेशे (गैर सैल्यूलोसिक फाइबर के अलावा) का भारतीय मुद्रा में अलग मूल्य क्या है ; और

(ख) देशीय कृत्रिम रेशे के उत्पादन को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) देश में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य कृत्रिम सैल्यूलोसिक फाइबर हैं : विसकोस स्टेपल फाइबर तथा रूपान्तरित स्टेपल फाइबर । उपलब्ध जानकारी के अनुसार कीमतें निम्नोक्त प्रकार है :--

मद	स्वदेशी (रु० कि.ग्रा.)	आयातित (सी आई एफ 1.5 डेनियर रु० प्रति कि.ग्रा.)
विस्कोस स्टेपल फाइबर	22·60	14.19
रूपान्तरित स्टेपल फाइबर	27·86	19·18

(ख) सरकार की नीति स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कृत्रिम फाइबरों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए कदम उठाए गये हैं ।

Measures to simplify Approval Process for Foreign Collaborations

390. DR. PRATAP WAGH :

SHRI SONTOSH MOHAN DEV :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a study jointly sponsored by the U.S. Department of State and a private organisation has drawn conclusions that the American business executives are increasingly turning to other countries for investment and collaboration due to lengthy time-consuming process in making decision in India ;

(b) if so, the details of the joint study; and

(c) the measures proposed by our Government to simplify the approval process for foreign collaboration ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) Presumably, the Hon. Members are referring to a recent study entitled "Doing Business Collaborations in India" prepared by an organisation called India International Inc,, for U.S. Department of State and the Overseas Private Investment Corporation. It, *inter-alia,* takes note of the stable political and sound economic environment offered by India for busieess collaborations, the country's rich resources and the substantial tax and other incentives provided by the Government to spur industrial growth and concludes that no profitable opportunities exist in India for U S. Technology transfers. The study, however, makes a reference to the time-consuming approval procedures, but it also recognises that the Government has simplified its procedures and has established much faster time-tables to approve foreign collaborations, according to the coantry's priorities.

(c) Several measures have been taken from time to time to simplify the approval procedures. These procedures are kept under constant review.